शिमला से प्रकाशित
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
शैल
निष्पक्ष एवं निर्भीक
साप्ताहिक समाचार
प्रकाशन का 47 वां वर्ष
www.facebook.com/shailsamachar
ई-पेपर
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक-36 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 29-05 सितम्बर 2022 मूल्य पांच रूपए

क्या जयराम सरकार ने अभी से चुनावी हार मान ली है

Dy.SP पदम ठाकुर की पुनर्नियुक्ति से उठा सवाल 2017 में सौंपे भाजपा के आरोप पत्र की प्रमाणिकता पर उठे सवाल

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री स्व.वीरभद्र सिंह के लम्बे समय तक सुरक्षा अधिकारी रहे डी.एस.पी. पदम ठाकुर 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए और जयराम ठाकुर की सरकार ने पहली सितम्बर को उन्हें उसी पद पर छ:माह के लिए पुनर्नियुक्ति दे दी। पदम ठाकुर एक योग्य अधिकारी हैं इसमें कोई दो राय नहीं है इस नाते उन्हें फिर से नियुक्त कर लिये जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसी भाजपा ने 2017 में जब यह विपक्ष में थी तब वीरभद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा आरोप पत्र राज्यपाल को सौंपा था। उस आरोप पत्र में वीरभद्र के सुरक्षा अधिकारी इन्हीं पदम ठाकुर और उनके कुछ परिजनों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाये गये हैं। बल्कि इन्हीं आरोपों के चलते जयराम ठाकुर की विजिलैन्स ने 27-08-2022 को धर्मशाला में पदम ठाकुर की बेटी अंजली ठाकुर के खिलाफ अपराध संहिता की धारा 420 और 120 बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (I)(II) और 13 (2) के तहत एफ. आई. आर. संख्या 10/2022 दर्ज भी की हुई है। परन्तु अब उन्हीं पदम ठाकुर को छह माह की पुनर्नियुक्ति देकर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में तूफान के हालात पैदा कर दिये हैं। स्मरणीय है कि जयराम सरकार 2017 में सौंपी अपनी चार्जशीट को कांग्रेस के खिलाफ एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करती आयी है। जब भी कांग्रेस ने जयराम सरकार के खिलाफ आरोप लगाने की बात की है तभी जयराम अपने 2017 में सौंपी गयी चार्जशीट का भय दिखाकर कांग्रेस को चुप करवाते आये हैं। लेकिन आज उसी आरोपपत्र के एक मुख्य पात्र बने अधिकारी को उन्हीं के व्यक्तिगत आग्रह पर पुनर्नियुक्ति देकर सबको चौंका दिया है। क्योंकि आने वाले चुनाव प्रचार में अब इसी आरोप पत्र पर कांग्रेस को घेरना संभव नहीं होगा। इस नियुक्ति के माध्यम से मुख्यमंत्री ने अपनी ही पार्टी से एक बड़ा हथियार छीन लिया है। वैसे भी इस आरोप पत्र पर अंजली ठाकुर के खिलाफ दर्ज हुई एफ.आई. आर. को छोड़कर और कोई बड़ी कारवाई सामने नहीं आयी है। पार्टी के भीतर इस पुनर्नियुक्ति पर क्या प्रतिक्रियाएं उभरती है या इस पुनर्नियुक्ति को रद्द कर दिया जाता है इसका पता तो आने वाले दिनों में चलेगा। लेकिन यह नियुक्ति की ही क्यों गयी। इसको लेकर राजनीति और प्रशासनिक हलकों में कयासों का दौर अवश्य चल निकला है। अब तक जितने भी चुनावी सर्वेक्षण सामने आये हैं। उन में किसी में भी भाजपा की सरकार नहीं बन पायी है। जिन निर्दलीय और कांग्रेसी विधायकों को भाजपा में शामिल करवाया गया है उन्हें पार्टी चुनावी टिकट दे पायेगी यह तक निश्चित नहीं है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री प्रो.प्रेम कुमार धूमल के अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा फैल गयी है और इसका कोई खण्डन नहीं आया है। इस चर्चा से यह सवाल उलझ गया है कि भाजपा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि नड्डा जयराम को लेकर कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया के प्रत्युत्तर में इशारे की बात ही कर पाये थे स्पष्ट नहीं कर सके थे। उधर एक समय जब जयराम ने कांग्रेस के प्रस्तावित आरोप का मुख मोड़ने के लिए भाजपा के पुराने आरोपों की जांच सी.बी.आई. को सौंपने की बात कही थी उसका अपरोक्ष में विक्रमादित्य सिंह ने सी.बी.आई./ई.डी. का हॉली लॉज में स्वागत की पोस्ट डाल कर जवाब दिया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आज सी.बी.आई से डरने वाला कोई नहीं है। इस सारे घटनाक्रम से अनचाहे ही यह संकेत चला गया है कि भाजपा के भीतर की तस्वीर कांग्रेस से भी ज्यादा धुंधली चल रही है। इस परिदृश्य में पदम ठाकुर की पुनर्नियुक्ति का आदेश आना इसी संदेश का वाहक माना जा रहा है कि पांच वर्षों में जयराम सरकार ने ईमानदारी से कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं किया है और आने वाले समय में कांग्रेस से भी इसी सौहार्द की अपेक्षा है। अन्यथा चुनावी संध्या पर ऐसे आदेशों का और क्या अर्थ निकाला जा सकता है। जिनकी मार अपने घर पर ज्यादा पढ़ने वाली हो जबकि इससे पहले लोक सेवा आयोग प्रकरण में मिली फजीहत की पीड़ा अभी कम नहीं हुई है।

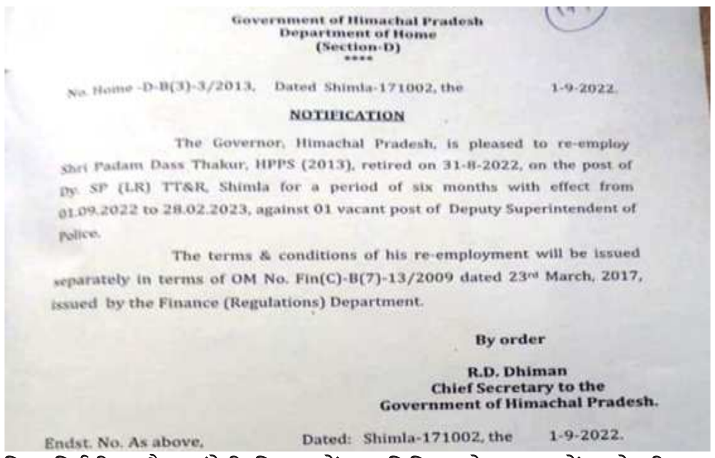
Government of Himachal Pradesh
Department of Home
(Section-D)
****

No. Home-D-B(3)-3/2013, Dated Shimla-171002, the 1-9-2022.

NOTIFICATION

The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to re-employ Shri Padam Dass Thakur, HPPS (2013), retired on 31-8-2022, on the post of Dy. SP (LR) TT&R, Shimla for a period of six months with effect from 01.09.2022 to 28.02.2023, against 01 vacant post of Deputy Superintendent of Police.

The terms & conditions of his re-employment will be issued separately in terms of OM No. Fin(C)-B(7)-13/2009 dated 23rd March, 2017, issued by the Finance (Regulations) Department.

By order

R.D. Dhiman
Chief Secretary to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. As above. Dated: Shimla-171002, the 1-9-2022.

यह है आरोप पत्र

– मुख्यमंत्री के निजी सुरक्षा अधिकारी को दिए लाभ

- मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ अधिकतर समय रहने वाले उनके सुरक्षा अधिकारी पदम ठाकुर, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय के अनेक भ्रष्ट कृत्यों के गवाह हैं, इसलिए उन्हें भी अनैतिक ढंग अपना कर अनेक फायदे पहुंचायेंगे। उनके खिलाफ दो शादियां करने का आरोप होने के बावजूद उन्हें गलत ढंग से प्रोमोशन दी गई।
- नियमो में विशेष छूट देकर पुलिस विभाग में ही कार्यरत उनकी पत्नी को पदोन्नति दी गई।
- उनकी एक बेटी को कांगड़ा सैन्ट्रल सहकारी बैंक में अनैतिक ढंग से नौकरी दी गई।
- दूसरी बेटी को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में नियमो की धज्जियां उड़ाकर नौकरी दी गई।
- बेटे आशीष ठाकुर को प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड में चोर दरवाजे से नौकरी पर रखा गया।

भाजपा की चुनाव प्रबन्धन कमेटियों से सांसद किशन कपूर और इन्दु गोस्वामी के नाम गायब

शिमला/शैल। आने वाले विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत भाजपा ने सत्रह कमेटीयों का गठन किया है। इन कमेटियों में प्रदेश के सारे वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गयी है। चुनाव दृष्टि पत्र समिति के संयोजक राज्यसभा सांसद प्रो. डॉक्टर सिकन्दर पूर्व कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को बनाया गया है। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अतिरिक्त जयराम मन्त्रीमण्डल के आधा दर्जन मन्त्रीयों सहित कुछ पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। इन कमेटीयों में भाजपा के सभी वरिष्ठ सदस्यों को नामित किया गया है। लेकिन इन सत्रह कमेटीयों से किसी एक में भी सांसद किशन कपूर और इन्दु गोस्वामी का नाम शामिल नहीं है। वैसे तो सांसद सुरेश कश्यप का नाम भी इन कमेटीयों में नही है लेकिन कश्यप क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है इसलिए वह स्वत: ही सभी कमेटियों के सदस्य हो जाते हैं। बल्कि वह सभी कमेटीयों की रिपोर्ट तलब कर सकते हैं।

परन्तु इन कमेटीयों में से किशन कपूर और इन्दु गोस्वामी के नाम गायब होना पार्टी के भीतर बाहर चर्चा का विषय बने हुए हैं। दोनों कांगड़ा से ताल्लुक रखते हैं और कांगड़ा में पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है। अब जब कांग्रेस विधायक एवं कार्यकारी अध्यक्ष रहे पवन काजल भाजपा में शामिल हुए तो कांगड़ा भाजपा के उत्साहित होने और काजल का स्वागत करने की बजाये एक तरह के रोष की स्थिति पैदा होना पार्टी हकीकत ब्यान करता है। बल्कि एक समय किश्न कपूर से मिलने जब कुछ कार्यकर्ता आ गये थे और उनके आने को पार्टी विरोधी गतिविधि करार देकर कुछ नेताओं ने कपूर की शिकायत तक कर दी थी। आज कपूर का नाम कमेटीयों में न आने से यह पुराने प्रकरण स्वत: ही चर्चित हो उठे हैं।

इसी तर्ज पर इन्दु गोस्वामी ने जब महिला मोर्चा द्वारा आपेक्षित महिला सम्मान सम्मेलन में धूमल को ज्यादा से ज्यादा मतों से जीताने की अपील की तो इस अपील को भी कुछ हल्कों में सहजता से नहीं लिया गया है। बल्कि वह सारे प्रकरण पुन: ताजा हो गये हैं जब इन्दु गोस्वामी ने अपने पदों से त्यागपत्र तक दे दिया था। यह त्यागपत्र देने के बाद ही वह राज्यसभा सांसद बनी है। नेतृत्व परिवर्तन की परिस्थिति में उनका नाम भी विकल्प के रूप में चर्चा में रहा है। इस परिदृश्य में आज कांगड़ा के इन दोनों सांसदों का नाम किसी भी कमेटी में न होना पार्टी के अन्दर की कहानी ब्यान कर देता है।

मॉनसून सीजन में नुकसान पर मुख्य सचिव की केंद्रीय टीम के साथ बैठक

शिमला/शैल। प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान अभी तक हुए नुकसान का आकलन करने पहुंची केंद्र की एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालय टीम ने मुख्य सचिव

आरडी धीमान और सभी संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर नुकसान की रिपोर्ट पर चर्चा की तथा इस संबंध में अंतरिम ज्ञापन प्राप्त किया। केंद्रीय टीम की अगुवाई कर रहे गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन) सुनील कुमार बर्णवाल और अन्य सदस्य धर्मशाला से तथा टीम के अन्य सदस्यों सुभाष कुमार और दीपशेखर सिंघल बिलासपुर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

इस अवसर पर मुख्य सचिव आरडी धीमान ने बताया कि प्रदेश सरकार के विशेष आग्रह पर पहली बार केंद्रीय दल ने मानसून सीजन के दौरान ही 28 से 30 अगस्त तक राज्य का दौरा किया है। इससे वास्तविक स्थिति के आकलन में मदद मिली है। मुख्य सचिव ने बताया कि अभी केंद्रीय दल को 1981.86 करोड़ रुपये के नुक्सान का अंतरिम ज्ञापन सौंपा गया है। मुख्य सचिव ने बताया कि इसमें लोक निर्माण विभाग को 957.09 करोड़ रुपये और जल शक्ति विभाग को 725.07 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। इसके अलावा अन्य विभागों तथा निजी संपत्ति की भी भारी क्षति हुई है। प्रदेश में अभी तक इस मानसून सीजन के दौरान आपदा से कुल 278 लोगों की मौत हुई है, जबकि 522 लोग घायल हुए हैं तथा 9 लोग अभी भी लापता हैं। 169 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 825 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। 72 दुकानें और 887 गौशालाएं भी तबाह हुई हैं। इस दौरान 587 पशु भी मारे गए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि यह केवल अंतरिम रिपोर्ट है और आने वाले दिनों में इन आंकड़ों में काफी वृद्धि की संभावना है, क्योंकि अभी मानसून सीजन के 20-25 दिन शेष हैं तथा कई स्थानों पर नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जिसकी अंतिम रिपोर्ट सीजन के अंत तक प्रस्तुत की जाएगी। इस रिपोर्ट में केंद्रीय दल के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे।

इस अवसर पर केंद्रीय टीम के अध्यक्ष सुनील कुमार बरनवाल ने बताया कि टीम के दो अलग-अलग समूहों ने कांगड़ा, चंबा, मंडी और कुल्लू जिलों के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक दौरा करके स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राहत शिविरों का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इन क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने राहत एवं बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना भी की। सुनील कुमार बर्णवालऔर टीम के अन्य सदस्यों ने रिपोर्ट के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे।

केंद्रीय टीम के साथ व्यापक चर्चा के बाद मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बरसात के मौसम के अंत तक नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाएं तथा फील्ड के अधिकारियों को सक्रिय करें। बैठक में राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने नुकसान के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की।

महाक्विज का छठा चरण 2 सितम्बर से आरम्भ होगा

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जनभागीदारी से सुशासन-हिमाचल का महाक्विज का छठा चरण 2 सितम्बर से आरम्भ होगा और 15 सितम्बर, 2022 तक चलेगा। वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया युवा खेल एवं वन विषय पर आधारित इस चरण का शुभारंभ अटल स्टेडियम नूरपुर से करेंगे।

उन्होंने बताया कि इस महाक्विज का शुभारंभ मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 11 मई, 2022 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर किया था। हिमाचल प्रदेश में पहली बार आयोजित किए जा रहे इस महाक्विज के पांच चरण पूरे हो चुके हैं, जिनमें 71,445 प्रतिभागी हिस्सा ले चुके हैं। कोई भी इच्छुक व्यक्ति इस महाक्विज में हिस्सा लेकर पुरस्कार जीत सकता है। महाक्विज में हिस्सा लेने के लिए माईगव हिमाचल पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया निःशुल्क है और इसका सातवां और आठवां चरण भी शीघ्र ही आरम्भ होगा।

ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किए जा रहे इस महाक्विज का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। महाक्विज के प्रत्येक चरण में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित दस सवाल हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में पूछे जाएंगे जिनका जवाब दो मिनट तीस सेकंड में देना होगा।

उन्होंने कहा कि महाक्विज के आठ चरण पूर्ण होने के उपरान्त पहला स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को 51,000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 21,000 रुपये और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। प्रत्येक चरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को भी एक-एक हजार रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी।

नेहरू युवा केंद्र द्वारा शिमला मे मनाया जाएगा युवा महोत्सव

शिमला/शैल। नेहरू युवा केंद्र शिमला, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जिला शिमला मे जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता के 75 वर्ष, लोगों का गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियां दर्शाने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष में आयोजित किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य देशभक्ति की भावना और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को फिर से जगाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है विविध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में लोगो को जागरूक करना, देश के युवा कलाकारों, लेखकों, फोटोग्राफरों और वक्ताओं को एक स्थान पर विशेषज्ञो के देखरेख मे एकत्र करना, जिला, राज्य और राष्ट्रीय मंचों पर युवा शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए युवाओं का एक सम्मेलन करना यह कार्यक्रम पहले जिला स्तर पर तथा उसके उपरांत राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित किया जाएगा।

यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र शिमला के द्वारा जिला मुख्यालय मे आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम मे 6 तरह के प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगे जिसमे जोकि निम्न प्रकार से हैं: 1. युवा कलाकार कैंप -पेंटिंग 2. युवा लेखक कैंप-कविताए 3. मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता 4. भाषण प्रतियोगिता 5. सांस्कृतिक कार्यक्रम- समूह कार्यक्रम 6. युवा संवाद सम्मेलन-इंडिया@2047। इस कार्यक्रम मे केवल वही प्रतिभागी भाग ले सकते हैं जो शिमला जिले के स्थायी निवासी हो। इस कार्यक्रम मे भाग लेने के लिए प्रतिभागी की आयु 15 साल से 29 साल होनी चाहिए। इस कार्यक्रम मे विजेता प्रतिभागियों के लिए इनाम राशि का भी प्रस्ताव है जिसके लिए प्रतिभागी का बैंक खाता होना आवश्यक है तथा विजेता प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय युवा उत्सव मे भाग लेने का मौका भी मिल सकता है।

इस कार्यक्रम के लिए अपना पूर्व पंजीकरण नेहरू युवा केंद्र शिमला मे करवाना 08 सितंबर से पहले करवाना आवश्यक है। युवा उत्सव से संबन्धित अधिक जानकारी के लिए नेहरू युवा केंद्र शिमला के जिला कार्यालय मे भी संपर्क किया जा सकता है। कार्यालय के दूरभाष संख्या-0177-2657178 या ई-मेल के माध्यम से भी nykshimla@gmail.com पर सुबह 10 से साँय 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। यह जानकारी प्रैस को नेहरू युवा केंद्र शिमला की जिला युवा अधिकारी मनीषा शर्मा ने दी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादकः जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकारः ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

अन्जना

केंद्र ने प्रदेश के लिए एसडीआरएफ की द्वितीय किश्त जारी की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य के लिए राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ) 2022-23 की दूसरी किश्त के रूप में 171.20 करोड़ रुपये जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने यह किश्त जारी करने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया था।

मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ की दूसरी किश्त जारी करने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा कि इसमें प्रदेश सरकार द्वारा भी 10 प्रतिशत यानि 19.20 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। इस तरह राज्य आपदा राहत निधि की द्वितीय किश्त 190.40 करोड़ रुपये हो जाएगी। इससे प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के दृष्टिगत प्रभावितों की सहायता के लिए समुचित सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा सकेगी। इससे अन्य राहत एवं पुनः निर्माण कार्य भी सुचारू रूप से चलाए जा सकेंगे।

मतदाता सूचियों के लिए दावे या आक्षेप 11 सितंबर तक

4 सितंबर को प्रत्येक मतदान केंद्र पर चलाया जाएगा विशेष अभियान

शिमला/शैल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्य 10 अक्तूबर तक पूरा कर लिया जाएगा।

राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्य 16 अगस्त से आरंभ किया जा चुका है। इस दौरान नए पात्र लोगों के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करने के दावे और अपात्र लोगों के नाम हटाने के संबंध में आपत्तियां निर्धारित प्रपत्रों पर प्राप्त की जा रही हैं। ये दावे या आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर निर्धारित की गई है।

प्रवक्ता ने बताया कि एक अक्तूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी अपने नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करवा सकते हैं। सभी पात्र लोगों के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करने के लिए 3 और 4 सितंबर को प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

प्रवक्ता ने बताया कि मतदाता सूचियों का प्रारूप सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कार्यालयों के अलावा प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी के पास भी उपलब्ध करवाया गया है। कोई भी पात्र नागरिक इन मतदाता सूचियों का निरीक्षण करके इनमें अपने नाम दर्ज होने की पुष्टि कर सकता है। अगर उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वह अपना नाम पंजीकृत करवाने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर 11 सितंबर तक आवेदन कर सकता है।

इसी प्रकार अपात्र व्यक्ति का नाम हटाने के लिए भी निर्धारित प्रपत्र पर आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल या वोटर हैल्पलाइन ऐप पर भी ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। मतदाता सूचियों में अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceohimachal.nic.in. पर भी की जा सकती है।

प्रवक्ता ने बताया कि मतदाता सूचियों के संबंध में 11 सितंबर तक प्राप्त दावों या आपत्तियों का निपटारा 26 सितंबर तक कर लिया जाएगा। इसके बाद 10 अक्तूबर को ये मतदाता सूचियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएंगी।

अगस्त माह में जीएसटी संग्रहण में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, युनूस ने बताया कि इस वित्त वर्ष में अगस्त माह के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अगस्त माह में 398 करोड़ रुपये जीएसटी संग्रहण किया गया है। उन्होंने कहा इस वित्त वर्ष के दौरान प्रथम पांच माह में जीएसटी संग्रहण पिछले वर्ष की समान अवधि के 1634 करोड़ रुपये के संग्रहण की तुलना में 2255 करोड़ रुपये रहा है।

उन्होंने कहा कि यह वृद्धि करदाताओं में कर अदायगी सम्बन्धी अनुपालना में सुधार तथा विभाग द्वारा किए गए विभिन्न प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रयासों तथा प्रवर्तन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से सम्भव हो पाई है।

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 25 प्रतिशत की वार्षिक संचयी वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए विभाग ने रिटर्न फाइलिंग में निरन्तर सुधार, रिटर्न की तीव्र छंटनी, जीएसटी ऑडिट को समय पर पूरा करना और मजबूत प्रवर्तन पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया है।

विभाग ने वर्तमान वित्त वर्ष में अपने रोड चौकिंग अभियान में पांच लाख 60 हजार ई-वे बिल सत्यापित किए हैं। विभाग स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और टैक्स हाट कार्यक्रम के तहत समयबद्ध रूप से हितधारकों के मुद्दों का निवारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस माह के दौरान हितधारकों को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि जागरूकता कार्यक्रमों से स्वैच्छिक अनुपालना में सुधार आने की सम्भावना है।

उन्होंने कहा कि विभाग टैक्स अधिकारियों के ज्ञान में वृद्धि तथा क्षमता निर्माण पर भी ध्यान केन्द्रित कर रहा है। गत छह माह के दौरान 400 कर अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा विभागीय पुनर्गठन की सैद्धान्तिक मंजूरी और प्रशिक्षित अधिकारियों के सशक्त प्रयासों से विभाग को राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य को बल्क ड्रग फार्मा पार्क के आवंटन के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य को बल्क ड्रग फार्मा पार्क आवंटित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है।

राज्य को बल्क ड्रग फार्मा पार्क आवंटित करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लिए राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना का आवंटन वास्तव में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह राज्य में कई वर्षों के लिए फार्मा फॉर्मूलेशन इकाइयों के प्रतिधारण के साथ-साथ स्थानीय रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों को बल्क ड्रग फार्मा पार्क आवंटित करने का मुख्य उद्देश्य घरेलू निर्माण, दवा सुरक्षा सुनिश्चित करना और चीन पर बल्क ड्रग की निर्भरता कम करना है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मार्च, 2020 को बल्क ड्रग पार्क योजना को मंजूरी दी थी और बाद में 21 जुलाई, 2020 को प्रस्ताव जमा करने के लिए मूल्यांकन मानदंड निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के फार्मा विभाग (डीओपी) द्वारा 1000 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत का 90 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना अवधि के दौरान राज्य सरकार ने अपेक्षित भूमि की पहचान करना शुरू कर दिया और जिला ऊना की हरोली तहसील के पोलियां, टिब्बीं, मल्लूवाल में 1,405 एकड़ भूमि का चयन किया गया। उन्होंने कहा कि पार्क की अनुमानित परियोजना लागत लगभग 1200 करोड़ रुपये है, जिसमें से सामान्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया जाएगा और इस पार्क में लगभग 8000 से 10,000 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 15 हजार से 20 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। फार्मा पार्क के लिए लगभग 100-120 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि निवेश पर उच्च प्रतिलाभ के प्रस्ताव में उपयोगिता शुल्क और अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में दस साल के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली, दस साल के लिए शून्य रख-रखाव शुल्क और गोदाम शुल्क के अलावा 33 साल के लिए एक रुपये प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष भूमि दर, स्टाम्प शुल्क में छूट, अधिकतम निवेश के उच्च रिटर्न को सुनिश्चित करने के प्रस्ताव में प्रति वर्ष 51 लाख रुपये तक के सावधि ऋण पर सात प्रतिशत ब्याज सबवेंशन और शुद्ध एसजीएसटी पर 70 प्रतिशत छूट की पेशकश की गई थी।

यह उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में 600 से अधिक फार्मा निर्माण इकाइयां हैं और राज्य में थोक दवा की वार्षिक मांग लगभग 30,000-35,000 करोड़ प्रतिवर्ष है। अब इस पार्क से थोक दवा की मांग को लागत प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकेगा जो फार्मा निर्माण इकाइयों की उत्पादकता और परिचालन क्षमता को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा यह पार्क पूरे देश में विशेष रूप से उत्तरी भारत की एपीआई जरूरतों को भी पूरा करेगा।

हिमाचल प्रदेश विज्ञान स्नातकों का केंद्र है और इस पार्क की कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को आराम से पूरा करेगा। इसके अलावा, इस परियोजना से संबंधित अन्य सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों जैसे आवास, टाउनशिप, पार्क की वाहन आवश्यकता आदि का राज्य की अर्थव्यवस्था पर गुणक और बहुआयामी प्रभाव होगा। यह पार्क पैकिंग, फार्मा फॉर्मूलेशन इत्यादि विभिन्न गतिविधियों में भी भारी निवेश को आकर्षित करेगा।

आयुष डॉक्टरों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगाः स्वास्थ्य मंत्री

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुर्वेद मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार डॉक्टरों की मांगों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है और पौने पांच वर्षों के दौरान उन्हें विभिन्न लाभ और सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

हिमाचल आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी संघ (एचएएमओए) के साथ संघ की विभिन्न मांगों पर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि आयुष चिकित्सकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को जमीनी स्तर तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने में आयुर्वेदिक चिकित्सक अमूल्य योगदान दे रहे हैं। सरकार ने भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए अतिरिक्त प्राथमिकता दी है और नए आयुष स्वास्थ्य केंद्र खोलकर तथा डॉक्टरों एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ के पद भरकर विभाग को मजबूत किया गया है।

इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री से आयुष चिकित्सकों को प्रारंभिक प्रवेश स्तर पर एलोपैथिक, दंत चिकित्सा और पशु चिकित्सकों के समान ही संवर्ग सेवाओं में शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने आयुष चिकित्सा अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने, सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि और स्नातकोत्तर नीति सहित कई अन्य मुद्दों को भी स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष उठाया।

डॉ. राजीव सैजल ने संघ के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और समयबद्ध तरीके से उचित निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में संघ के अध्यक्ष डॉ. शिव गौतम, महासचिव डॉ. राजेश्वर कंवर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला के शिक्षक संघ के साथ भी बैठक की और आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. माणिक सोनी ने स्वास्थ्य मंत्री को विभिन्न मांगों से अवगत कराया।

एचपीटीडीसी के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान प्रदान किया जाएगा:जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के कर्मचारियों को राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर प्रथम जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडल की 158वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। निदेशक मण्डल के इस निर्णय से निगम के 1300 से अधिक कर्मचारियों को प्रति वर्ष 12.40 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों को उनका बकाया समय पर प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने इस वर्ष अप्रैल से जुलाई माह के दौरान 45.91 करोड़ रुपये की आय और लगभग 11.79 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि निगम को हाउसमैन, यूटिलिटी वर्कर, सुरक्षा गार्ड/चौकीदार, विशेषज्ञ रसोइया, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, राजमिस्त्री, माली और बेलदार आदि की श्रेणियों में आवश्यकता आधारित श्रम शक्ति को काम पर रखने के लिए अधिकृत किया जाएगा ताकि होटल इकाइयों की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन इकाइयों में ग्राहकों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित होंगी।

मुख्यमंत्री ने निगम की कार्यप्रणाली में व्यावसायिकता लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कर्मचारियों को प्रशिक्षण, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आदि के माध्यम से प्रेरित कर कार्य संस्कृति में बदलाव लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को खाद्य उत्पादन व सेवा आदि में निपुणता के लिए इन-हाउस प्रशिक्षण और रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास निगम के उपक्रमों के प्रचार के लिए वेबसाइट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रभावी अभियान चलाया जाना चाहिए।

एचपीटीडीसी के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

बैठक में मुख्य सचिव आर.डी. धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पश्चिमी हिमालयी समशीतोष्ण वृक्षोद्यान परियोजना की सलाहकार समीति की बैठक आयोजित

शिमला/शैल। वन विभाग के वन्यप्राणी प्रभाग द्वारा वित्त पोषित पश्चिमी हिमालयी समशीतोष्ण वृक्षोद्यान परियोजना की सलाहकार समीति की बैठक प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक हिमाचल प्रदेश राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस परियोजना का क्रियान्वयन हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, पंथाघाटी द्वारा किया जा रहा है।

इस अवसर पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्यप्राणी) राजीव कुमार ने कहा कि इस परियोजना के अन्तर्गत शिमला में वृक्ष-उद्यान विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वृक्ष-उद्यान में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्यान में पानी की सुविधा व आग जैसी घटनाओं से निपटने के लिए भी उचित प्रबन्ध किए जाएंगे।

बैठक के दौरान डॉ. संजीव, निदेशक व वैज्ञानिक हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, पंथाघाटी एवं पश्चिमी हिमालयी समशीतोष्ण वृक्षोद्यान परियोजना के प्रभारी डॉ. वनीत जिष्टू ने परियोजना की संकल्पना, उद्देश्य व परियोजना के अन्तर्गत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की रूपरेखा पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

डॉ. वनीत जिष्टू ने बताया कि इस परियोजना के माध्यम से शिमला शहर में हरित स्थलों को वृक्षोद्यान द्वारा बढ़ाया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शिमला व इसके आस-पास के क्षेत्रों में पौधे रोपित करना, पेड़ों को स्वस्थ रखना, शहरी जैव विविधता का संरक्षण, स्थानीय वृक्षों की प्रजातियों को रोपित करके पारिस्थितिकी संतुलन बनाना, लोगों को जागृत करना, पौध रोपण द्वारा शहरी वनीकरण व वाटिकाएं तैयार करना आदि है।

बैठक में अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्यप्राणी) अनिल ठाकुर, मुख्य अरण्यपाल (वन्यप्राणी) के. थीरूमल, निदेशक हिमालयन अनुसंधान ग्रुप डॉ. लाल सिंह सहित विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक व अधिकारी भी उपस्थित थे।

केंद्र सरकार ने दी 229 करोड़ रुपये की शिमला मल शोधन परियोजना को स्वीकृति

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि केंद्र सरकार ने शिमला शहर के लिए 229 करोड़ रुपये की मल शोधन परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना वर्ष 2025 तक पूर्ण की जाएगी तथा इससे शिमला शहर की आबादी को आने वाले 30 वर्षों तक मल निकासी की सुविधा मिलेगी।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस परियोजना के अन्तर्गत शिमला शहर में नई मल निकासी व्यवस्था स्थापित करने तथा पुरानी लाइनों को स्तरोन्नत करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र सरकार के केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियान्त्रिकी संगठन को भेजी गई थी। जिसके फलस्वरूप केंद्र सरकार से 229 करोड़ रुपये की इस परियोजना को स्वीकृति प्राप्त हुई हैं। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रोग्राम-फॉर-रिजल्ट के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटिड द्वारा शहर में लगभग 230 किलोमीटर पाइपें बिछाई जाएंगी ताकि शहर के सभी घरों में मल निकासी की सुविधा प्रदान करने के लिए एक नई व्यवस्था बनाई जा सके। इस परियोजना से शिमला शहर में मल निकासी सुविधा में शामिल न हो सके लोगों को भी सुविधा मिलेगी।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान मल निकासी व्यवस्था को स्तरोन्नत किया जाएगा जिसके तहत बिछाई गई पुरानी लाइनों को चार इंच व्यास से छः इंच व्यास में बदला जाएगा। यह परियोजना शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटिड द्वारा वर्ष 2025 तक चरणबद्ध रूप से पूर्ण की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लागू होने के बाद शिमला शहर में मल निकासी के लिए सेप्टिक टैंक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह परियोजना शिमला शहर के ढली तथा मशोबरा के शेष बचे कुछ भागों को मल निकासी सुविधा से जोड़ेगी।

जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा,
तब तक मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा,
कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है..!!
......स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद संविधान से हटा देना चाहिये?

भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके गुहार लगाई है कि संविधान के उद्घोष से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के शब्दों को हटा दिया जाये। डॉ. स्वामी की याचिका से पहले भी मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.आर. सेन दिसम्बर 2018 में यह फैसला दे चुके है कि भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिये। जस्टिस सेन के इस निर्देश के खिलाफ कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय गये थे। जस्टिस गोगोई की पीठ ने मेघालय उच्च न्यायालय को नोटिस भी जारी किये थे। लेकिन बाद में जस्टिस गोगोई ने यह कहकर मामला बन्द कर दिया था कि इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब डॉ. स्वामी की याचिका अगर स्वीकार हो जाती है तो संविधान संशोधन का रास्ता कानूनी तौर पर साफ हो जाता है। इस से स्वतः ही देश हिन्दू राष्ट्र हो जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह हो जायेगा कि इस समय देश में जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उनका भविष्य क्या हो जायेगा? क्योंकि इस समय जो दल सत्तारूढ़ है वह लगभग मुस्लिम मुक्त है। संसद में उसके पास शायद कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं है। शायद भाजपा शासित राज्यों में मुस्लिम विधायक भी नहीं के बराबर हैं। पहली बार है कि केंद्रीय मन्त्रीमण्डल में कोई मुस्लिम मन्त्री नहीं है। यही नहीं ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि सत्तारूढ़ दल का नेतृत्व कांग्रेस और क्षेत्रीय दल मुक्त भारत का नारा दे रहा है। सत्तारूढ़ दल व्यवहारिक रूप से अपने को मुस्लिम विरोधी कहलाने में संकोच नहीं कर रहा है। भारत बहुभाषी और बहुत धर्मी देश है यही बहुलता इसकी विशेषता है। लेकिन जब सत्तारूढ़ दल के प्रयास यह हो जायें कि वह देश में किसी भी दूसरे दल की उपस्थिति ही न चाहता हो तो और इसके लिये भ्रष्टाचार के नाम पर जांच एजेंसियों का खुला दुरुपयोग होने के आरोप लग जायें तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे बची रह पायेगी? यह सवाल आने वाली पीढ़ियों के सामने एक बड़ा सवाल बनकर जवाब मांगेगा यह तय है। क्योंकि इस समय हिन्दू-मुस्लिम का मुद्दा जिस तरह से लगातार बड़ा बनाया जा रहा है उससे देश में एक बार फिर बंटवारे जैसे हालात उभरते जा रहे हैं जो कालान्तर में बहुत घातक सिद्ध होंगे यह भी तय है। देश ने आजादी के लड़ाई अंग्रेज के शासन के खिलाफ लड़ी है मुस्लिम के विरुद्ध नहीं यह इतिहास का एक नितान्त कड़वा सच है। देश का बंटवारा भी अंग्रेज को भगाने के लिये स्वीकार किया गया था। उस समय भी कुछ लोग स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध कर रहे थे और इस विरोध के अदालती प्रमाण स्वयं डॉ. स्वामी ने देश के सामने रखे हैं। बाद में इसी लोकतंत्र में यह विरोध करने वाले भी देश के शीर्ष पदों तक पहुंचे हैं। क्योंकि विरोध के स्वर अंग्रेजों के प्रायोजित शब्द थे। लेकिन दुर्भाग्य से यही विरोध के स्वर नये कलेवर में आज फिर उठने शुरू हो गये हैं और मुस्लिम विरोध इनका बड़ा हथियार बन गया है। इस परिदृश्य में आज लोकतंत्र के लिये सही में बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। आज यह दावा किया जा रहा है कि भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इंग्लैंड को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में यह सवाल पूछा जाना आवश्यक हो जाता है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्र भी पी पी पी मोड पर प्राइवेट सैक्टर को देने की नौबत क्यों आ रही है। साधारण खाद्यानों पर भी जीएसटी क्यों लगानी पड़ी है? बेरोजगारी ने इस दौरान पिछले सारे रिकॉर्ड क्यों तोड़ दिये हैं। नई शिक्षा नीति की भूमिका में यह क्यों कहना पड़ा है कि हमारे बच्चे खाड़ी के देशों में बतौर हैल्पर ज्यादा समायोजित हो पायेंगे। ऐसे दर्जनों सवाल है जो सरकारी दावों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। क्योंकि आर्थिकी उत्पादन में बढ़ोतरी से नहीं वरन स्थापित संसाधनों को प्राइवेट क्षेत्र के हवाले करने से बड़ी है। इस परिदृश्य में यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि यदि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को संविधान के उद्घोष से हटाने की अदालती स्वीकृति मिल जाती है तो उसके बाद किस तरह का सामाजिक वातावरण निर्मित होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी के सर्वोत्कृष्ट उपयोग से हिमाचल में हुए क्रांतिकारी सुधार

शिमला। राज्य के लोगों को पारदर्शी और उत्तरदायी सुशासन प्रदान करने के अपने संकल्प के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के अधिकतम उपयोग को लगातार बढ़ावा दिया है। जन शिकायतों के त्वरित समाधान के अलावा प्रशासन में सुधार और लोगों को समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आईटी सक्षम सेवाएं शुरू की गई हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं ने राज्य सरकार को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, अनुसंधान और सार्वजनिक सेवा वितरण आदि में त्वरित और कुशल सेवाएं देने में सक्षम बनाया है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम नीति-2019 अधिसूचित की है जिसका उद्देश्य प्रदेश को आईटी, आईटीईएस (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं) और इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम) कंपनियों के लिए पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाना है। यह नीति इन क्षेत्रों के लिए अत्यधिक कुशल जनशक्ति पूल के अलावा इन उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ढांचागत सहायता प्रणाली बनाने की परिकल्पना भी करती है।

इस नीति से इन क्षेत्रों में स्टार्ट-अप और उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा और व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने तथा ई-गवर्नेंस ढांचे की स्थापना में एक मील पत्थर साबित होगा। साथ ही एक समय-सीमा में डिजिटल सेवा वितरण सुनिश्चित कर एक अनुकूल वाणिज्यिक माहौल भी तैयार होगा।

कागज रहित कार्यालयों को सक्षम बनाने के लिए प्रदेश में विभिन्न विभागों में ई-ऑफिस परियोजना लागू की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के साथ-साथ 57 निदेशालयों, 11 उपायुक्त कार्यालय, 10 पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के अलावा 26 फील्ड कार्यालयों सहित अब तक 5715 अधिकारियों और अधिकारियों को ई-ऑफिस के अंतर्गत शामिल किया गया है। सरकार का विचार सभी कार्यालयों को कागज रहित मोड में स्थानांतरित करके ई-ऑफिस के छत के नीचे लाना है जिसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग विभिन्न विभागों को लगातार प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

आईटी निवेश को बढ़ावा देने के लिए शिमला और धर्मशाला के गग्गल में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के दो केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को सोलन जिले में वाकनाघाट स्थित आईटी पार्क में स्थानीय युवाओं के कौशल विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने दिसंबर, 2020 में इसकी आधारशिला रखी थी।

हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। सरकारी क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 14 दिसंबर, 2021 को धर्मशाला में ड्रोन मेला आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न ड्रोन निर्माताओं ने भाग लिया। राज्य के आईटी विभाग ने गरुड़ परियोजना की भी परिकल्पना की है जिसका उद्देश्य ड्रोन के उपयोग से प्रशासन और सुधार है। इसे 27 दिसंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मंडी यात्रा के दौरान शुरू किया था।

क्षेत्रीय अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, नेरचौक और धर्मशाला से टांडा मेडिकल कॉलेज तक दवाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन का सफल ट्रायल रन किया गया है। आईटी विभाग ने ड्रोन कंपनियों के सहयोग से कुल्लू व चंबा ज़िलों के दुर्गम एवं दूर-दराज़ के इलाकों में ड्रोन का उपयोग कर दवाओं की डिलीवरी के लिए प्रूफ ऑफ कान्सेप्ट (पीओसी) का आयोजन किया। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मार्च, 2022 में आईटीआई, शाहपुर, कांगड़ा में हिमाचल के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 शिकायतों और सुझावों को दर्ज करने या जानकारी प्राप्त करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत शिकायत प्रणाली है। एमएमएसएस हेल्पलाइन में अब तक कुल 4,39,456 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 4,24,782 शिकायतों का समाधान संबंधित नागरिकों की संतुष्टि के अनुसार किया गया है।

आईटी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संबंधित विभागों के साथ 160 (केंद्र की 73 व राज्य की 87) योजनाओं की पहचान की जिनमें से 59 योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) लागू किया गया है। 74 राज्य योजनाओं की अधिसूचना संबंधित विभागों द्वारा जारी कर दी गई है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 59 योजनाओं के तहत 13.83 लाख लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 2283.58 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।

आईटी विभाग ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान ऑनलाइन डिलीवरी के लिए हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल में 31 नई सेवाएं शामिल की हैं। इनमें से 28 सेवाएं बागवानी विभाग और तीन शहरी विकास विभाग की हैं। अब इस पोर्टल के माध्यम से राजस्व, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, शहरी विकास आदि सहित विभिन्न विभागों की 96 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे आवेदनों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है और इसके माध्यम से प्रतिदिन औसतन 4500 आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

इससे क्षेत्रीय सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है और नागरिकों को घर बैठे समय पर सेवा प्रदान करने में मदद मिली है, जिससे उनका समय और पैसा भी बचा है। इसके अलावा, पंचायत स्तर पर सेवाओं के वितरण की सुविधा के लिए इस पोर्टल की 68 सेवाएं लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई हैं।

आईटी विभाग ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत हिमस्वान (हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क) नामक सुरक्षित नेटवर्क भी तैयार किया है जो खंड स्तर तक सरकार के सभी विभागों को सुरक्षित नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करता है। 2314 सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम हिमस्वान के माध्यम से जोड़े गए हैं।

भारत, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना

शिमला। इस साल भारत ने 670 अरब डॉलर यानी 50 लाख करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया। भारत ने हर चुनौती से पार पाते हुए 418 अरब डॉलर यानी 31 लाख करोड़ रुपये के वस्तु निर्यात का नया रिकॉर्ड बनाया।

पिछले आठ वर्षों में 1 अरब डॉलर के बाजार मूल्यांकन वाली 100 से भी अधिक कंपनियां सृजित हुई हैं और हर महीने नई कंपनियां इनमें जुड़ती जा रही हैं। पिछले आठ वर्षों में सृजित हुए इन यूनिकॉर्न का बाजार मूल्यांकन आज लगभग 150 अरब डॉलर यानी तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपये है।

वर्ष 2014 के बाद पहले 10,000 स्टार्ट-अप्स तक पहुंचने में हमें लगभग 800 दिन लगे थे। 10,000 नए स्टार्ट-अप्स को हाल ही में इस सूची में शामिल होने में 200 दिनों से भी कम का समय लगा। पिछले आठ वर्षों में देश में स्टार्ट-अप्स की कुल संख्या कुछ सौ से बढ़कर आज 70,000 हो गई है। ये स्टार्ट-अप्स भारत के कई राज्यों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी फैले हुए हैं। इसके अलावा लगभग 50 से भी अधिक विभिन्न प्रकार के स्टार्ट-अप्स विभिन्न उद्योगों से जुड़े हुए हैं। ये स्टार्ट-अप्स देश के हर राज्य और 650 से भी अधिक जिलों में फैले हुए हैं। लगभग 50 प्रतिशत स्टार्ट-अप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों में हैं।

डिजिटल क्रांति उस अद्भुत गति का उत्कृष्ट उदाहरण है जिससे भारत ने विगत वर्षों में काम किया है। वर्ष 2014 में हमारे देश में केवल 6.5 करोड़ ब्रॉडबैंड ग्राहक थे। आज उनकी संख्या 78 करोड़ से भी अधिक हो गई है।

वर्ष 2014 में एक जीबी डेटा की कीमत लगभग 200 रुपये हुआ करती थी। आज इसकी कीमत घटकर सिर्फ 11-12 रुपये रह गई है।

वर्ष 2014 में देश में बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर की कुल लंबाई 11 लाख किमी थी। अब देश में बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर की कुल लंबाई 28 लाख किमी को पार कर गई है।

सरकार ने भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है।

पिछले सात-आठ वर्षों में भारत सरकार ने डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से सिर्फ एक क्लिक से लाभार्थियों के खातों में पैसे भेजे हैं। हमने डीबीटी के माध्यम से जो राशि भेजी है वह 22 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक है।

हम एक-दूसरे को मदद प्रदान करने वाली कनेक्टिविटी की बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। सागरमाला, भारत माला, पर्वत माला, बंदरगाह आधारित विकास।

आज भारत सामाजिक एवं भौतिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश का साक्षी बन रहा है। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जहां आम सहमति का माहौल बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर नई

आज भारत जी-20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।
स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर के मामले में आज भारत दुनिया में नंबर वन है।
इंटरनेट यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है।
आज भारत वैश्विक खुदरा सूचकांक में दूसरे पायदान पर है। भारत पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है।
विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भारत में ही है।
'नवाचार सूचकांक' में भारत की रैंकिंग बेहतर हो गई है।

स्वास्थ्य नीति को लागू करने का काम चल रहा है। आज भारत में छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने के उद्देश्य से रिकॉर्ड संख्या में नए हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। भारत में आज मेट्रो कनेक्टिविटी पर जितना काम हो रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में नए मोबाइल टॉवर लगाए जा रहे हैं और 5जी भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है।

हमें इस देश की जनता पर पूरा भरोसा है कि सुशासन के लिए जो भी तकनीक लाई जाएगी, उसे वह अपनाएगी और सराहेगी। जनता के इस भरोसे का नतीजा दुनिया के सबसे बेहतरीन डिजिटल ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के रूप में सबके सामने है। कुल वैश्विक डिजिटल लेन-देन का 40 प्रतिशत हिस्सा भारत में किया जा रहा है। आज रेहड़ी-पटरी वाले और दूर-दराज के गांवों से लेकर शहरों के विभिन्न मोहल्ले में रहने वाले देशवासी 10-20 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक के लेन-देन आसानी से कर रहे हैं।

समावेशी विकास

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में करीब दो लाख करोड़ रुपये अंतरित किए गए हैं।

अब तक देश के 3 करोड़ गरीब लोगों को उनके पक्के और नए घर मिल चुके हैं, जहां उन्होंने रहना शुरू कर दिया है। आज देश के 50 करोड़ से अधिक गरीब लोगों के पास 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। आज देश के 25 करोड़ से अधिक गरीब लोगों के पास 2 लाख रुपये प्रत्येक का दुर्घटना बीमा और सावधि बीमा है। आज देश के करीब 45 करोड़ गरीबों के पास जन धन बैंक खाते हैं।

पीएम स्वनिधि के तहत, देश के 35 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक मदद मिली है।

मुद्रा योजना के तहत देशभर के छोटे उद्यमियों को 20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण दिया गया है। ऋण प्राप्त करने वालों में करीब 7 करोड़ ऐसे उद्यमी हैं, जिन्होंने पहली बार कारोबार शुरू किया है और नए उद्यमी बने हैं। यानी, मुद्रा योजना की मदद से पहली बार 7 करोड़ से ज्यादा लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं। 70 प्रतिशत ऋण, महिला उद्यमियों को दिए गए हैं।

'आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना' से लाखों छोटे उद्योगों को मदद मिली है। एक अध्ययन के अनुसार, इस योजना ने करीब 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां बचाई हैं।

एमएसएमई का अर्थ है- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिकतम समर्थन!

एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने पिछले आठ साल के दौरान बजट में 650 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी की है।

इस क्षेत्र से 11 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए एमएसएमई आज अधिकतम रोजगार प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

इसलिए, जब 100 वर्षों का सबसे बड़ा संकट हमारे सामने आया, तो हमने अपने छोटे उद्यमों को बचाने और उन्हें एक नई ताकत देने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत एमएसएमई के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपये सुनिश्चित किए हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, इससे करीब 1.5 करोड़ नौकरियां बचाई गई।

कारोबार में आसानी

देश अब श्रम कानूनों में बदलाव और सुधार करने के साथ इसे सरल बना रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 29 श्रम कानूनों को बदलाव कर चार सरल श्रम संहिताओं में रखा गया है।

1500 से अधिक कानूनों को समाप्त करके, 30,000 से अधिक अनुपालनों को कम करके, तथा कंपनी अधिनियम के कई प्रावधानों को अपराध-मुक्त करके, यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत की कंपनियां न केवल आगे बढ़ें बल्कि नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें।

जीएसटी ने अब केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न प्रकार के करों के जाल को समाप्त कर दिया है। सरल बनाने की इस प्रक्रिया का परिणाम देश भी देख रहा है। अब जीएसटी संग्रह का हर महीने एक लाख करोड़ रुपये को पार करना सामान्य बात हो गयी है।

एक राष्ट्र

हमने नीतिगत स्थिरता, समन्वय और कारोबार में आसानी पर जोर दिया है। गुजरे वक्त में हमने हजारों अनुपालनों और पुराने कानूनों को समाप्त किया है। हमने अपने सुधारों के साथ भारत को एक राष्ट्र के रूप में मजबूत करने का काम किया है। चाहे एक राष्ट्र-एक टैक्स जीएसटी हो, एक राष्ट्र-एक ग्रिड, एक राष्ट्र-एक मोबिलिटी कार्ड या फिर एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड हो, ये सभी प्रयास हमारी ठोस और स्पष्ट नीतियों की ही झलक हैं।

नवाचार और उद्यमिता संबंधी कौशल को बढ़ावा देने वाले नए इंटरफेस

'सरकार ही सब कुछ जानती है और सरकार ही सब कुछ करेगी' इस कार्य संस्कृति को पीछे छोड़ते हुए कि अब हमारा देश 'सबका प्रयास' की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए आज भारत में कई नए इंटरफेस तैयार किए जा रहे हैं और बीआईआरएसी जैसे प्लेटफॉर्म्स को सशक्त बनाया जा रहा है। चाहे स्टार्ट-अप्स के लिए स्टार्टअप इंडिया अभियान हो, अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए इन-स्पेस हो, रक्षा स्टार्ट-अप्स के लिए आईडेक्स हो, सेमीकंडक्टर के लिए भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन हो, युवाओं में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हो, या फिर बायोटेक स्टार्ट-अप एक्सपो हो, सरकार इनोवेटिव संस्थानों के जरिए इस उद्योग जगत की उत्कृष्ट प्रतिभा को एक मंच पर ला रही है और सामूहिक प्रयासों की भावना को बढ़ावा दे रही है। इन प्रयासों से देश को बड़ा फायदा हो रहा है। देश को अनुसंधान और शिक्षा से नई सफलताएं मिल रही हैं, असल दुनिया के नजरिए में ये उद्योग जगत मदद कर रहा है, और सरकार आवश्यक नीतिगत वातावरण और बुनियादी ढांचा प्रदान कर रही है।

युवाओं के सामने आ रही हर बाधा को दूर कर लगातार सुधार किया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र को निजी उद्योगों के लिए खोलना, अंतरिक्ष उद्योग में निजी भागीदारी, आधुनिक ड्रोन नीति तैयार करना, भू-स्थानिक डेटा दिशानिर्देश तैयार करना, दूरसंचार-आईटी क्षेत्र में 'कहीं से भी काम' की सुविधा देना, इन सबके साथ सरकार हर दिशा में काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि भारत के निजी क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' का माहौल तैयार किया जाए, ताकि देश का निजी क्षेत्र भी 'ईज ऑफ लिविंग' में उसी प्रकार से देशवासियों की मदद कर सके।

भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का श्रेय हमारे श्रमिकों को

शिमला। प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जैसे अनेक प्रयासों ने श्रमिकों को एक तरह का सुरक्षा कवच दिया है। ऐसी योजनाओं की वजह से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मन में ये भाव जगा है कि देश उनके श्रम का भी उतना ही सम्मान करता है।

देश के इन प्रयासों का कितना प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, इसके साक्षी हम कोरोनाकाल में भी बने हैं। 'इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम' इसकी वजह से लाखों छोटे उद्योगों को मदद मिली है। एक अध्ययन के मुताबिक, इस स्कीम की वजह से करीब डेढ़ करोड़ लोगों का रोजगार जाना था, वो नहीं गया, वो रोजगार बच गया। कोरोना के दौर में EPFO से भी कर्मचारियों को बड़ी मदद मिली, हजारों करोड़ रुपए कर्मचारियों को एडवांस के तौर पर दिए गए। और साथियों, आज हम देख रहे हैं कि जैसे जरूरत के समय देश ने अपने श्रमिकों का साथ दिया, वैसे ही इस महामारी से उबरने में श्रमिकों ने भी पूरी शक्ति लगा दी है। आज भारत फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था बना है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे श्रमिकों को ही जाता है।

देश के हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए, किस तरह काम हो रहा है, उसका एक उदाहरण 'ई-श्रम पोर्टल' भी है। ये पोर्टल पिछले साल शुरू किया गया था, ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आधार से जुड़ा नेशनल डेटाबेस बन सके। मुझे खुशी है कि इस एक साल में ही, इस पोर्टल से 400 अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले करीब 28 करोड़ श्रमिक जुड़ चुके हैं। विशेष रूप से इसका लाभ कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स को, प्रवासी मजदूरों को, और डॉमेस्टिक वर्कर्स को मिल रहा है। अब इन लोगों को भी Universal Account Number जैसी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। श्रमिकों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, 'ई-श्रम पोर्टल' को National Career Service असीम पोर्टल और उद्यम पोर्टल से भी जोड़ा जा रहा है।

बीते आठ वर्षों में हमने देश में गुलामी के दौर के, और गुलामी की मानसिकता वाले क़ानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। देश अब ऐसे लेबर क़ानूनों को बदल रहा है, रीफॉर्म कर रहा है, उन्हें सरल बना रहा है। इसी सोच से 29 लेबर क़ानूनों को 4 सरल लेबर कोड्स में बदला गया है। इससे हमारे श्रमिक भाई-बहन न्यूनतम सैलरी, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विषयों पर और सशक्त होंगे। नए लेबर कोड्स में Inter&State migrant labours की परिभाषा को भी सुधारा गया है। हमारे प्रवासी श्रमिक भाई-बहनों को 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' जैसी योजना से भी बहुत मदद मिली है।

देश का श्रम मंत्रालय अमृतकाल में वर्ष 2047 के लिए अपना विज़न भी तैयार कर रहा है। भविष्य की जरूरत है- Flexible work places, work from home ecosystem- भविष्य की जरूरत है- Flexi work hours, हम flexible work place जैसी व्यवस्थाओं को महिला श्रमशक्ति की भागीदारी के लिए अवसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

शिक्षक दिवस पर 15 शिक्षक राज्य पुरस्कार से सम्मानित

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह के दौरान 15 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार और वर्ष 2021 के एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षक को सम्मानित किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हमारी संस्कृति में शिक्षक को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर पुरस्कृत किए गए शिक्षकों ने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, जोकि सभी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज को निरंतर योगदान और मार्गदर्शन देता है और यही कारण है कि समाज उन्हें हमेशा याद करता है। राज्यपाल ने कहा कि आज वह जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसमें उनके शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके लिए वह हमेशा अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

राज्यपाल ने संतोष व्यक्त किया कि सभी पुरस्कार विजेता शिक्षकों ने पाठ्यक्रम से आगे बढ़ते हुए समर्पण भाव से काम किया है और इसलिए उन्हें सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों ने जीवन में समाज के लिए कुछ न कुछ योगदान दिया और वे समाज के लिए प्रेरणा बने हैं। राज्यपाल ने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है, इसलिए शिक्षकों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अलग तरह से काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों में आनंद के साथ पढ़ाने की भावना विकसित की जानी चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि आज की शिक्षा प्रणाली 'स्मृति परीक्षण' तक सीमित हो गई है और इसमें अन्य गुणों का परीक्षण नहीं किया जाता है। जबकि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 इसके बिलकुल विपरीत है और इससे हर बच्चे में मौजूद गुणों को सामने लाने में मदद मिलेगी। राज्यपाल ने कहा कि बच्चों में पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें पढ़ने की अभिरुचि भी विकसित की जानी चाहिए।

उन्होंने जीवन में एक अच्छा इंसान बनने पर बल देते हुए कहा कि शिक्षा के माध्यम से इन्सान को नैतिक मूल्य प्राप्त करने चाहिए ताकि वे किसी भी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकें।

राज्यपाल ने इस अवसर पर स्मारिका का विमोचन भी किया।

शिक्षक दिवस पर बधाई देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि यह शिक्षकों के लिए एक विशेष दिन है, इसलिए यह औपचारिकता नहीं बल्कि शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी पर ध्यान देने का अवसर है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मानव समाज के विकास की पहली सीढ़ी है, जो राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रदान मानव जाति की सबसे बड़ी सेवा है और इसे महादान भी कहा गया है।

उन्होंने कहा कि सम्मानित होने वाले प्रत्येक शिक्षक की एक प्रेरणादायक कहानी है। इनमें से कुछ शिक्षकों ने कोरोना काल में हर चुनौती का सामना करते हुए छात्रों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देने के लिए सशक्त प्रयास किए और वे अन्य के लिए भी प्रेरणास्त्रोत बनें।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल को हिमाचली टोपी, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया।

प्रधान सचिव शिक्षा देवेश कुमार ने शिक्षा विभाग की विभिन्न गतिविधियों एवं उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा डॉ. वीरेंद्र शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर जिला सोलन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कहलोग के प्रधानाचार्य कमल किशोर, जिला शिमला के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घनाहट्टी के प्रधानाचार्य सतीश कुमार, जिला कुल्लू के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बरान के प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह ठाकुर, जिला सिरमौर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सराहां के प्रधानाचार्य सुरिंदर सिंह, जिला कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलियार के प्रवक्त (पीजीटी) हिन्दी कुलदीप सिंह, जिला शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुपवी के प्रवक्ता (अर्थशास्त्र) राय सिंह रावत, जिला मण्डी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भंगरोटू के डीपीई विनोद कुमार, जिला सोलन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामपुर के टीजीटी (मेडिकल) प्रदीप कुमार, जिला सिरमौर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय लाना मियून के टीजीटी (नॉन मेडिकल) निशि कांत, जिला मण्डी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धरोटधार के टीजीटी (नॉन मेडिकल) हरीश कुमार ठाकुर, जिला मण्डी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोहर के कला अध्यापक चमन लाल, जिला ऊना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बसाल के प्राच्य शिक्षक (ओटी), चमन लाल, जिला कांगड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भलाड़ के मुख्य शिक्षक संजीव कुमार, जिला बिलासपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटला की जेबीटी अध्यापिका अच्छर लता, जिला हमीरपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पलवीं के जेबीटी अध्यापक मोहन लाल शर्मा और जिला शिमला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय हजल की जेबीटी अध्यापिका अनुराधा को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर की छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न स्कूलों के शिक्षक और विद्यार्थी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय

शिमला/शैल मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत शोधार्थियों को पंजीकरण की तिथि से तीन वर्षों तक 3000 रुपये मासिक फैलोशिप दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए यह योजना आरंभ की गई है।

मंत्रिमंडल ने सीसीएस (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43-बी को अपनाते हुए बच्चा गोद लेने वाली राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की।

बैठक में सोलन जिले की कृष्णगढ़ उप तहसील के अंतर्गत मंडेसर और ढकरियाना में दो नए पटवार सर्कल खोलने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने ऊना जिले की उप तहसील हरोली के तहत लालड़ी में नया पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के हथोल तथा टयालू में नए पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया गया।

बैठक में बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के बस्सी में नया कानूनगो वृत्त खोलने को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला की इंदौरा तहसील के अंतर्गत थापकौर और नूरपुर तहसील के अंतर्गत कमनाला में नए पटवार वृत्त बनाने को सहमति प्रदान की।

बैठक में सिरमौर जिले की नौहराधार तहसील में पटवार वृत्त चराना को विभाजित कर नया पटवार वृत्त सैल (चुनवी स्थित शायला) खोलने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के झंडूता विधान सभा क्षेत्र के बल्हसीणा में नया डिग्री कालेज खोलने का निर्णय लिया। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने के साथ-साथ 5 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान करने को भी मंजूरी दी।

इसी प्रकार चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र के मसरूंड में भी नया डिग्री कालेज खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों के सृजन एवं भरने तथा पांच करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान करने का निर्णय भी लिया गया।

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम नई दिल्ली के पक्ष में ब्लॉक सरकारी गारंटी 35 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर के परिसर में पुलिस थाना बिलासपुर के अंतर्गत नई पुलिस चौकी स्थापित करने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों के सृजन एवं भरने को सहमति प्रदान की।

बैठक में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मानदेय में प्रथम सितंबर, 2022 से प्रतिमाह 900 रुपये वृद्धि करने का निर्णय लिया गया, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात लगभग 510 एसपीओ को लाभ प्राप्त होगा।

मंत्रिमंडल ने सोलन नगर निगम क्षेत्र में बेतरतीब पार्किंग, वाहनों की भीड़ और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स के कारण आने वाली विभिन्न समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के राजकीय उच्च विद्यालय खीणी, शाला निशार, शोध अधार और कांढा तथा बिलासपुर जिला के उच्च विद्यालय साई ब्राह्मणा, निहारखन वासला, भगेड़, पनेहड़ा और कल्लर तथा सोलन जिला के राजकीय उच्च विद्यालय भटोलीकलां को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त मंडी जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय ज्वालापुर, थाड़ी, खलबूट और डोभा तथा बिलासपुर जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय दिगथली, जामला, सवाना, सिदसूह, हरितल्यांगर, मंडयाली और भटेड़ तथा सोलन जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर को राजकीय उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा इन नव स्तरोन्नत विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बैला और चूरढ़ को राजकीय उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा इनके लिए 16 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय अमरोआ को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने व इसके लिए तीन पद सृजित कर भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के नूरपुर में इंडोर स्टेडियम, मंडी जिला के जंजैहली स्टेडियम तथा शिमला जिला के खेल छात्रवास दत्तनगर/इंडोर स्टेडियम रामपुर में नव निर्मित खेल अधोसंरचना के संचालन के लिए 12 पदों पर कर्मियों की सेवाएं लेने को भी स्वीकृति प्रदान की।

सरकार बनने पर पहला फैसला ओपीएस बहाली का होगा:सुक्खू

शिमला/शैल। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी बीते लबे समय से आंदोलन पर है। वहीं बीते तीन सप्ताह से वे शिमला में क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हिमाचल कांग्रेस इन कर्मचारियों की मांगो को लगातार उठा रही है। शनिवार को कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू अनशन पर बैठे कर्मचारियों से मिलने पहुंचे। सुखविंदर सुक्खू अनशनकारी कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन नरेश चौहान भी थे। सुक्खू ने कर्मचारियों को आश्वास्त किया है कि सरकार बनते ही कर्मचारियों की पुरानी पैंशन बहाली की जाएगी।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पहले दिन से सरकारी कर्मचारियों के साथ खड़ी है। कर्मचारी चाहे किसी भी विभाग, यूनिवर्सिटी, सरकारी समितियों और निगमों का हो, कांग्रेस सभी कर्मचारियों के साथ है। उन्होंने कहा कि तीन माह बाद जब उनकी सरकार सता में आएगी तो सबसे पहले वे ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारीयों का हिमाचल के विकास में बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दस गारंटियों में भी सबसे पहले ओल्ड पैंशन बहाली है।

उन्होंने साफ कहा कि ये घोषणा पत्र नहीं बल्कि यह गारंटी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा के घोषणा पत्र का भी अध्ययन किया है और पाया है कि उसमें कोई भी वादे पूरे नहीं किए हैं। प्रचार कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते वे यहां आये ताकि कर्मचारियों को आश्वस्त किया जा सके। उन्होंनें कहा कि जहां जहां भी ये कर्मचारी आंदोलन पर बैठेंगे हैं, वहां कांग्रेस के नेता और विधायक जाएंगे और यह आश्वस्त करेंगे कि कांग्रेस उनके साथ है और तीन माह बाद सरकार बनने पर पुरानी पैंशन बहाल की जाएगी।

सुक्खू ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद सोशल सिक्योरिटी लागू करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस है कि जयराम सरकार की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने जयराम सरकार पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप भी लगाये है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

कांग्रेस की गारंटीयो के ब्रह्मास्त्र में उलझी भाजपा

मन्त्रीयों से लेकर नीचे हर नेता जवाब देने के लिए उतरा मैदान में

शिमला/शैल। राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी वायदों के रूप में मुफ्ती योजनाओं की घोषणाएं किया जाना कितना जायज है? क्या इनकी कोई सीमा तय होनी चाहिये? ऐसी घोषणाओं का पूरी आर्थिकी पर कितना और क्या असर पड़ता है? यह सवाल हमारे देश में भी श्रीलंका की स्थिति के बाद चर्चा और चिन्तन का विषय बने हुए हैं। सबसे पहले वरिष्ठ नौकरशाहों के एक बड़े वर्ग ने प्रधानमन्त्री के समक्ष यह विषय उठाते हुए यह कहा था कि यदि राज्यों को ऐसी घोषणाओं से न रोका गया तो कुछ राज्यों की हालात कभी भी श्रीलंका जैसी हो जायेगी। इसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया और वहां उसे तीन जजों की पीठ को सौंप दिया गया है। आशा की जा रही है कि गुजरात और हिमाचल विधानसभा के चुनाव से पूर्व ही शायद कोई सुप्रीम निर्देश आ जाये। यह विषय कितना गंभीर और व्यापक है इसको सही परिप्रेक्ष में समझने के लिए आर्थिकी से जुड़े कुछ आंकड़े ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है क्योंकि केन्द्र से लेकर राज्यों तक हर प्रदेश कर्ज में इतना डूब चुका है कि सभी एफ आर बी एम के मानकों को अंगूठा दिखा चुके हैं। इन मानकों के अनुसार कोई भी राज्य जी डी पी के तीन प्रतिशत से लेकर पांच प्रतिशत तक ही कर्ज ले सकता है। जून में जो तेरह राज्यों की रिपोर्ट आर बी आई ने जारी की थी उसके मुताबिक कुछ राज्य 240% से 347% कर्ज ले चुके हैं। कैग रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश का कर्ज भार ही जी. डी.पी. के करीब 40% पहुंच गया है

इस परिदृश्य में आज जब हिमाचल के चुनावों के परिप्रेक्ष में भाजपा, कांग्रेस और आप में इन मुफ्ती की घोषणाओं को लेकर आपस में होड़ लग गयी है तब प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ सवाल जनहित में सार्वजनिक मंच से इन तीनों दलों से पूछे जाने आवश्यक हो जाते हैं। क्योंकि मुफ्ती योजनाओं की घोषणाओं की शुरूआत आप ने की थी। आप को मात देने के लिये जयराम सरकार ने पहले 60 यूनिट और फिर 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा कर दी। लेकिन सरकार यहीं नहीं रुकी महिलाओं को बस किरायों में छूट का ऐलान कर दिया गया। घोषणाओं की इस दौड़ में कांग्रेस ने दस गारंटीयों का ऐलान करके सरकार को पीछे छोड़ दिया। लेकिन सरकार ने कांग्रेस की गारंटीयों के जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से चलायी जा रही 31 योजनाओं की सूची जारी करके यह दावा किया है कि सरकार कांग्रेस की दस गारंटीयों से पहले ही लोगों को 31 योजनाओं के माध्यम से सब कुछ दे चुकी है। मंत्रीयों से लेकर नीचे तक भाजपा का हर नेता कांग्रेस को जवाब देने के काम में लग गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस की गारंटीयों से सही में सरकार और भाजपा परेशान हो उठी है। क्योंकि कांग्रेस की गारंटीयों का सच तो सरकार बनने के बाद पता चलेगा जबकि भाजपा के दावों का सच तो अभी जमीन पर पता चल जायेगा।

जयराम सरकार पर सबसे बड़ा आरोप सदन के भीतर और बाहर प्रदेश को कर्ज के गर्त्त में धकेलने का लगता आ रहा है। जयराम ठाकुर ने अपने पहले बजट भाषण में सदन में यह जानकारी रखी थी कि उनको विरासत में करीब 46,000 करोड का कर्ज मिला है। यह भी कहा था कि वीरभद्र सरकार ने 18,000 करोड सीमा से अधिक लिया है। अभी मानसून सत्र में दी गयी जानकारी के मुताबिक कुल कर्ज 63,735 करोड़ है और जीडीपी 1,75,173 करोड़। 2021-22 और 2022-23 में विभिन्न योजनाओं के तहत केन्द्र से 25,524 करोड सहायता के रूप में और 912 करोड के रूप में मिले हैं। केन्द्रिय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी के रूप में 35,454 करोड मिला है। इस तरह से 2021-22 और 2022-23 में केन्द्र से कुल 60,978 करोड मिला है जबकि दोनों वर्षों का कुल बजट एक लाख करोड़ के अधिक का है। इन दो वर्षों में राज्य के अपने साधनों से करीब 24,000 करोड सरकार को मिला है। इस तरह केन्द्र और राज्य के अपने साधनों से बजट दस्तावेजों के मुताबिक 85,085 करोड मिला जबकि खर्च एक लाख करोड से अधिक हुआ और यह कर्ज लेकर पूरा किया गया।

कैग रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में केन्द्रिय सहायता के नाम पर कुछ योजनाओं में कोई पैसा सरकार को नहीं मिला है। शायद इसी कारण से सौ योजनाओं पर सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं कर पायी है। 2019 में स्कूलों में बच्चों को वर्दियां तक नहीं दी जा सकी है। जबकि 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए और इस वर्ष के बजट में सरकार का कुल बजट अनुमानों से करीब सोलह हजार करोड़ अधिक खर्च हुआ है और यह खर्च जुटाने के लिए कर्ज लेने के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं रहा है। बल्कि बजट दस्तावेजों के मुताबिक सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां भी शुद्ध ऋण होती है। इस तरह यदि बजट के आंकड़ों का सही से अध्ययन किया जाये तो कुल कर्ज का आंकड़ा एक लाख करोड से पार हो जाता है। आज जब राजनीतिक दल अभी से चुनावी गारंटीयां लेकर आ रहे हैं तब उनसे प्रदेश की इस बजटीय स्थिति पर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। राजनीतिक दलों से कर्ज की सही स्थिति की जानकारी को लेकर प्रश्न पूछे जाने चाहिये। यह स्पष्ट किया जाना चाहिये की बिना कर्ज लिये और टैक्स लगाये वायदों को कैसे पूरा किया जायेगा।

आखिर ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ जयराम सरकार कारवाई क्यों नहीं कर पा रही है

शिमला/शैल। जयराम सरकार का स्वास्थ्य विभाग पहले दिन से ही विवादों में चल रहा है। जब किसी बेनाम कार्यकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री शान्ता कुमार के नाम एक खुला पत्र लिखा था। यही पत्र आगे चलकर पूर्व मन्त्री रविन्द्र रवि के खिलाफ मामला दर्ज करने का कारण बना। इसी प्रकरण में विपिन परमार को स्वास्थ्य मंत्री से हटाकर विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। राजीव बिन्दल विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाकर पार्टी अध्यक्ष बनाये गये। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के विवादों ने बिन्दल की पार्टी अध्यक्षता भी छीन ली और तत्कालीन स्वास्थ्य निदेशक को जेल तक पहुंचा दिया। स्वास्थ्य विभाग की सप्लाईयों को लेकर भी कुछ मामले बने हैं सचिवालय की ब्रांच तक इस लपेट में आ चुकी है। जिस विभाग को लेकर इतना कुछ पूर्व में घट चुका हो उसके बारे में हवा में भी अगर कहीं कोई कानाफूसी चल रही हो तो उसे भी बहुत गंभीरता से लिया जायेगा यह स्वभाविक है। हिमाचल देश का एक बड़ा फार्मा उद्योग केन्द्र है। यहां पर बनने वाली दवाइयों की सप्लाई भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में होती है दवाइयों के निर्माण और उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चितता बनाये रखने की जिम्मेदारी सरकार के दवा नियंत्रक की होती है।

लेकिन हिमाचल में बनने वाली दवाइयों के सैंपल फेल होते रहते हैं। विधानसभा पटल तक यह मामले गूंज चुके हैं। सरकार ऐसी दवा निर्माता कंपनियों की सूची तक सदन में रख चुकी है। लेकिन इन कंपनियों के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी होने से ज्यादा कारवाई नहीं हो पायी है। विपक्ष भी सदन में प्रश्न पूछने तक ही अपनी भूमिका केन्द्रित रखने से आगे नहीं बढ़ा है। इससे जनता में स्वाभिवक रूप से यह सवाल उठ रहे हैं कि प्रदेश का फार्मा उद्योग राजनीतिक दलों के लिये चुनावी चन्दे का कोई बड़ा साधन तो नहीं है। क्योंकि प्रदेश के दवा नियंत्रक मरवाह के खिलाफ 500 करोड़ की संपत्ति होने के आरोप एक एम. सी. जैन लम्बे अरसे से लगाते आ रहे हैं। मरवाह के खिलाफ जांच की मांग प्रधानमंत्री से भी कर चुके हैं। जैन के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय भी सरकार को जांच के निर्देश दे चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री का सचिवालय प्रधानमन्त्री के निर्देशों के बावजूद इस पर कारवाई करने में क्यों असमर्थ हो रहा है यह लगातार रहस्य बनता जा रहा है। अब 14-08-2022 को पुनः जैन ने प्रधानमंत्री को शिकायत भेजी है जो पाठकों के सामने यथास्थिति रखी जा रही है ताकि पाठक स्वयं इसकी गंभीरता का अनुमान लगा सकें।

No.: MC/ABC/2022/473

Dated: 12.08.2022

To

Shri Narender Modi Ji
Hon'ble Prime Minister
Govt. of India
7, Lok Kalyan Marg,
New Delhi-110001.

विषय: नवनीत मारवाह ड्रग कन्ट्रोलर हिमाचल प्रदेश, बद्दी, जिला सोलन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के चार महीने बाद भी जांच नहीं होने के विषय में पुनः रिमाईन्डर पत्र एवं बद्दी स्थित सरकारी रिकार्ड को नवनीत मरवाहा से किसी उच्च अधिकारी की कस्टडी में लेने हेतु पत्र।

श्रीमान जी,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि मैने एक शिकायत पत्र नवनीत मरवाहा, प्रदेश ड्रग कन्ट्रोलर हिमाचल प्रदेश बद्दी के पद पर पिछले 10 साल से भी अधिक समय से आसीन के बारे में दिनांक 28.04.2022 एवं 04.06.2022 को शिकायत आपके कार्यालय में की थी एवं नवनीत मरवाहा के काले कारनामों के बारे में अवगत करवाया था कि किस तरह से नवनीत मरवाहा कुछ ही समय में करोडों रूपया इकट्ठा करके भ्रष्टाचार के माध्यम से मालामाल हो गया है। उक्त शिकायतों में मैने नवनीत मरवाहा का सम्पूर्ण ब्यौरा दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं कुछ और विवरण नवनीत मरवाहा के बारे में संलग्न कर रहा हूँ जो निम्न प्रकार से है। किस तरह से कुछ फार्मा उद्योगपति नवनीत मरवाहा को रिश्वत देकर अमीर बन रहे हैं एवं लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।

1. पुष्कर फार्मा काला अम्ब: जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश स्थित उद्योग नवनीत मरवाहा के आर्शीवाद से मोटी रिश्वत की बदौलत चल रहा है। Odisha State Medical Corporation द्वारा Black listed/Debarred किया गया।
उत्तर:- ड्रग विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।
1(a). Tamilnadu Medical Corporation वर्ष 2021-22 के टैन्डर के उपरान्त फर्म का निरिक्षण किया गया एवं उक्त Technical Tender Committee की रिपोर्ट के सन्दर्भ में फर्म As per GMP दवाईयों के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है।
उत्तर: विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।
1(b). इसके अतिरिक्त कई अन्य प्रदेशों में भी उक्त फर्म का Debarred/Black list विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किया गया परन्तु विभाग द्वारा GMP Certificate / Marketing Standing Certificate / Non Conven Certificate उक्त फर्म को धडल्ले से दिया जा रहा है।
2. Attens Lab काला अम्ब के जाली दस्तावेज: उक्त फर्म जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह भी नवनीत मरवाहा के आर्शीवाद एवं मोटी रिश्वत की रकम के आधार पर चल रही है।
2(a).उक्त फर्म को जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.01.2019 को Bureau of Pharma Public Sector undertaking of Medicals, New Delhi द्वारा फर्म के विरूद्ध जाली कागजात निविदा में लगाए जाने पर फर्म को 5 वर्ष के लिए Black listed एवं Criminal Action का आदेश पारित किया गया।
2(b). ड्रग विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। फर्म में इसके अतिरिक्त कई अन्य काले कारनामें नवनीत मरवाहा के कारण चल रहे हैं।
3. Tamilnadu Medical Corporation द्वारा जारी की गई रिपोर्ट: निविदा में हिमाचल प्रदेश स्थित 30 फर्मों द्वारा निविदा में भाग लिया गया जिसमें Technical Committee द्वारा जारी की गई लिस्ट जिसमें बताया गया है कि कुछ कम्पनियां जो GMP के मुताबिक दर्वाइयों का निर्माण नहीं कर रही हैं। विवरण के मुताबिक आठ कम्पनियां हैं। परन्तु विभाग द्वारा पुनः सभी Certificate GMP/Marketing Standing Certificate / Non Conviction Certificate प्रतिदिन जारी किया जा रहा है। केवल रिश्वत की मोटी रकम के बल पर हो रहा है। जिनका विवरण संलग्न है।

इसके अतिरिक्त दिसम्बर 2021 से जनवरी 2022 की List of Drugs as per not of standard quality / spouri / misbranded / Adulterated की लिस्ट भी संलग्न है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह हिमाचल प्रदेश में स्थित फार्मा कम्पनियां नवनीत मरवाहा को धन देकर जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है एवं विभाग द्वारा कोई एक्शन/कार्यवाही न करना जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ के लिए उत्साह बढ़ाता है एवं जनता के स्वास्थ्य को भगवान भरोसे छोड़ा जा रहा है।

4. Orison Pharma International, Kala Amb:- Excise and Taxation Deptt. Himachal Pradesh द्वारा एवं पंजाब पुलिस द्वारा काला अम्ब स्थित दो फार्मा कम्पनियों जिनके मालिक एक ही है, NDPS के तहत मुकदमा दर्ज किया एवं करोडों रूपयों की नशे की दवाईयां एवं पाऊडर बरबाद किया एवं लाईसैन्स कैन्सल करने का आदेश Excise Deptt. हि.प्र. द्वारा दिया गया। परन्तु ड्रग विभाग हिमाचल प्रदेश बद्दी द्वारा कोई भी संज्ञान न लेते हुए केवल उक्त Narcotic Drug की items approval निलम्बित कर दी। दोनों कम्पनी आज भी धडल्ले से बेरोक-टोक चल रही हैं। **NDPS Case की कापी संलग्न है।**
5. Digital Vision, Kala Amb: काला अम्ब स्थित फार्मा कम्पनी Digital Vision द्वारा निर्मित बच्चों के syrup से सैंकडों बच्चे जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त देश के अनेकों हिस्सों में मर गए। PGI Chandigarh एवं अन्य देश के सभी Medical College एवं CDL कलकता द्वारा भी उक्त कम्पनी द्वारा निर्मित दवाई में बच्चों के मरने की पुष्टि की है। उक्त कम्पनी के मालिक श्री पुरूषोतम एवं उनके दो सुपुत्र कोनिक गोयल एवं मोनिक गोयल हैं। कम्पनी आज भी बेरोक-टोक चल रही है। माननीय हि.प्र. हाईकोर्ट द्वारा जमानत भी Reject कर दी गई थी। माननीय CJM नाहन की अदालत में यह एफ.आई.आर. अभी विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त इसी गोयल परिवार ने एक कम्पनी काला अम्ब में Vellinton Health Care के नाम से नया लाईसैंस apply किया। वह विभाग द्वारा जारी कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जिस कम्पनी में काला अम्ब NDPS Act के तहत कार्यवाही हुई वह भी श्री पुरूषोतम गोयल का भाई है। उसका नाम राकेश गोयल है। यह कम्पनी भी विभाग की मेहरबानी से चल रही है। इसमें Blood Relation का कोई भी Objection नहीं है। दोनों भाईयों की सभी कम्पनियों का केस माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं देश के विभिन्न उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जबकि Vellinton Health Care के मालिक मानिक गोयल एवं अन्य पर अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। कम्पनी आज भी धडल्ले से बेरोक-टोक चल रही हैं।
6. Health Biotech Baddi द्वारा Covid-19 के दौरान Remidesivir जो कि भारत सरकार द्वारा केवल Export के लिए बनाने हेतु अनुमति प्रदान की थी परन्तु उक्त कम्पनी के Directors एवं अन्य लोगों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में उक्त इन्जैक्शन की बिक्री पर Black marketing के विषय में उक्त कम्पनी के Director के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अन्य प्रदेशों जैसे हरियाणा, चण्डीगढ़, केरल, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में मुकदमें दर्ज किए गए, परन्तु ड्रग विभाग हिमाचल प्रदेश बद्दी द्वारा सभी मुकदमों को दरकिनार करते हुए उक्त कम्पनी धडल्ले से चल रही है। यह मानवता के लिए भी बहुत बुरी बात है। **कापी संलग्न है।** कम्पनी आज भी धडल्ले से बेरोक-टोक चल रही हैं।

कृपया उक्त सभी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सभी तथ्यों की जांच उच्च अधिकारियों से करवाने की कृपा करें एवं जांच से पहले नवनीत मरवाहा से सारा विभागीय रिकार्ड जोकि नवनीत मरवाहा के पास है वह किसी उच्च अधिकारी की कस्टडी में रखा जाए क्योंकि कुछ रिकार्ड नवनीत मरवाहा द्वारा नष्ट / खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। अन्य भी सारा संदिग्ध रिकार्ड नष्ट कर दिया जाएगा क्योंकि नवनीत मरवाहा के पास ऐसा दस्तावेज है जोकि New Drug Approval of Products, WHO GMP/COPP के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज जो कि केवल नवनीत मरवाहा की Personal Custody में हैं।

यह दस्तावेज प्रदेश में अन्य जिला एवं माडल स्तर पर नियुक्त Asstt. Drug Controller के रिकार्ड में भी नहीं है। क्योंकि यह दस्तावेज केवल नवनीत मरवाहा द्वारा केवल मोटी रकम लेकर कम्पनियों को दिए जाते हैं जिनका जिला स्तर पर उक्त फर्मों के रिकार्ड में न होना पाए जाने पर नक्ली दस्तावेज / Forged Document कह दिय जाता है एवं फर्मों को Black mail भी किया जाता है।
सभी दस्तावेज संलग्न हैं।

प्रार्थी
एम.सी. जैन
393, सैक्टर 8, हुड्डा
अम्बाला शहर-134003